**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2992**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**ऊर्जा क्षेत्र में तत्काल आवश्यक सुधार**

**2992. श्री भुवनेश्वर कालिताः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों तथा वैश्विक तेल तथा गैस मुख्य कार्यकारियों के बीच पारस्परिक संवाद करने हेतु एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पारस्परिक संवाद के दौरान यह महसूस किया गया कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में काफी असमानता है तथा इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (घ):** प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में  नीति आयोग ने दिनांक 09 अक्‍तूबर, 2017 को दुनियाभर के तेल और गैस सीईओज की एक बैठक का समन्‍वय किया था।  उपरोक्‍त बैठक में तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए थे जिनमें अन्‍य बातों के साथ साथ सभी प्रकार की ऊर्जा के लिए समान अवसर उपलब्‍ध कराने का प्रावधान करना, पूर्वी और पूर्वोत्‍तर भारत के प्रचुर संसाधन वाले क्षेत्रों को नेशनल ग्रिड से जोडने पर जोर देना, देश के लिए कार्यनीतिक भंडारों को पूरा करने हेतु विभिन्‍न विकल्‍पों को ढ़ंढना, तेल और गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने की आवश्‍यकता तथा संयुक्‍त उद्यमों और प्रौद्योगिकी अंतरण द्वारा कोल बेड मिथेन और कोल गैसीयकरण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवोन्‍मेष कार्य किया जाना शामिल है।

सरकार द्वारा यथा परिकल्‍पित नेशनल ग्रिड का उद्देश्‍य नए भारत में गैस आधारित और स्‍वच्‍छ ईंधन अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देना है और इससे   प्राकृतिक गैस की उपलब्‍धता के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्‍त करने में मदद मिलेगी और देशभर में हरित ईंधन उपलब्‍ध होगा। देश के पूर्वी भाग में गैस पाइपलाइन के विकास को गति देने और उसे नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए सरकार ने 2655 कि.मी. लंबी जगदीशपुर-हलदिया/बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के निर्माण के लिए गेल को 5176 करोड़ रुपए का आंशिक पूंजी अनुदान (अर्थात्‍ 12,940 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजीगत लागत का 40%) अनुमोदित किया है।  इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने पूर्वोत्‍तर गैस पाइपलाइन नामत: बैरौनी-गुवाहाटी गैस पाइपलाइन परियोजना (लगभग 670 कि.मी.) के विकास के लिए गेल को प्राधिकृत किया है, जो मौजूदा राष्‍ट्रीय गैस ग्रिड के साथ पूर्वात्‍तर राज्‍यों को जोड़ने का एक गेटवे होगा और इससे पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा।  इसके अलावा, 5 सीपीएसईज नामत: ओएनजीसी,ओआईएल, गेल, आईओसीएल तथा एनआरएल ने एक संयुक्‍त उद्यम कंपनी का गठन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए हैं, जो 8 पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में गैस पाइपलाइन (लगभग 1500 कि.मी.) में गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य करेगी।

\*\*\*\*\*